

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3408

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

महाराष्ट्र में राजमार्गों का डिजिटलीकरण

†3408. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजमार्गों का डिजिटलीकरण करके वास्तविक समय की निगरानी, स्मार्ट टोलिंग, वाहन से अवसंरचना (वी2आई) प्रणालियों और सड़कों के परिसंपत्ति प्रबंधन के माध्यम से राजमार्गों को इंटेलिजेंट मोबिलिटी कॉरिडोर में परिवर्तित करने की पहल की है;

(ख) उक्त पहल के अंतर्गत डिजिटलीकरण के लिए जनजातीय और दूर-दराज के जिलों सहित महाराष्ट्र में कितने राजमार्ग पैकेजों का चयन किया गया है और इसके लिए कितना बजट दिया गया है;

(ग) क्या भू-टैग रखरखाव स्मार्ट टोल और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजनाएं मौजूद हैं और अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार को सभी नए राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों में डिजिटल राजमार्ग पहल को कब तक पूर्ण रूप से लागू किए जाने और प्रथम प्रगति रिपोर्ट 2025-26 में जनजातीय और पिछड़े जिलों के ब्यौरे को शामिल किए जाने का अनुमान है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) स्मार्ट टोलिंग के संबंध में, सभी 4 लेन और उससे अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग की योजना बनाई गई है। एमएलएफएफ टोलिंग प्रणाली के अंतर्गत, गैन्ट्री पर लगे उच्च प्रदर्शन वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) रीडर और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों का उपयोग मौजूदा फास्टैग प्रणाली के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क की कटौती के लिए किया जाता है। संलग्न सूची के अनुसार, बैरियर रहित टोलिंग पर आधारित मल्टी-लेन फ्री फ्लो के लिए 16 टोल प्लाजा आवंटित किए गए हैं। सरकार का विचार जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों सहित सभी 4 लेन और उससे अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों पर एमएलएफएफ टोलिंग को चरणबद्ध तरीके से लागू करना है। वर्तमान में, महाराष्ट्र राज्य में पुणे-नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग-60 पर स्थित चालकवाड़ी टोल प्लाजा और हिवारगांव पावसा टोल प्लाजा को एमएलएफएफ टोलिंग के तहत आवंटित किया गया है।

इसके अलावा, देश में 113 भीड़भाड़ वाले राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा की निगरानी भी जीआईएस आधारित टोल भीड़ निगरानी समाधान के माध्यम से की जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर फुटपाथ की स्थिति और अन्य राजमार्ग परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए, समय-समय पर एनएसवी (नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन) सर्वेक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण, एआई आधारित निरीक्षण आदि किए जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर, संबंधित संविदाकारों/रियायतग्राहियों के माध्यम से फील्ड इकाइयों द्वारा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक मरम्मत और रखरखाव किया जा रहा है।

'महाराष्ट्र में राजमार्गों का डिजिटलीकरण' के संबंध में एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी के द्वारा दिनांक 12.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3408 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	टोल प्लाजा	एनएच / राज्य
1.	घरौंदा टोल प्लाजा	हरियाणा में एनएच-44
2.	चोरयासी टोल प्लाजा	गुजरात में एनएच-48
3.	दौलतपुरा टोल प्लाजा	राजस्थान में एनएच-48
4.	मनोहरपुरा टोल प्लाजा	राजस्थान में एनएच-48
5.	शाहजहाँपुर टोल प्लाजा	राजस्थान में एनएच-48
6.	मुंडका टोल प्लाजा	दिल्ली में यूईआर-II
7.	बोरियाच टोल प्लाजा	गुजरात में एनएच-48
8.	नेमिली टोल प्लाजा	तमिलनाडु में एनएच-48
9.	चेनासमुद्रम टोल प्लाजा	तमिलनाडु में एनएच-48
10.	परनूर टोल प्लाजा	तमिलनाडु में एनएच-45
11.	कासेपल्ली टोल प्लाजा	आंध्र प्रदेश में एनएच-44
12.	अमकाथाडु टोल प्लाजा	आंध्र प्रदेश में एनएच-44
13.	मरूर टोल प्लाजा	आंध्र प्रदेश में एनएच-44
14.	चालकवाड़ी टोल प्लाजा	महाराष्ट्र में एनएच-50
15.	हिवारगांव पावसा टोल प्लाजा	महाराष्ट्र में एनएच-50
16.	बदरपुर फरीदाबाद टोल प्लाजा	हरियाणा में एनएच-19
